इस्पात सलाहकार समिति

३७७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दि० ३० मार्च, १९६२ को **इस्पात सलाहकार समिति की बैठक** में इस्पात **नियंत्रण में ढील** देने के लिये जो सुझाव प्रस्तुत किये गये थे उनमें से कितनों पर विचार किया जा चुका है और किन-किन सुझावों को सरकार ने मान लिया है ;

(ख) शेष को न मानने के क्या कारण हैं ;

(ग) लघु उद्योगों की इस्पात की कुल मांग कितनी है और उस की सरकार किस अंश तक पूर्ति कर रही है ; और

(घ) पूर्ति में अधिक वृद्धि की दिशा में क्या रुकावटें हैं और वे कैसे दूर हो सकेंगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इस्पात नियंत्रण में ढील देने के लिये दो सुझाव रखे गये थे :—

(१) काली प्लेन चादरों (१४ गेज से पतली), गैलवेनाइज्ड प्लेन, गैलवेनाइज्ड कौरूगेटिड चादरों और तारों पर से कोटा सिस्टम हटाना और

(२) स्टाक-होल्डर स्तर पर मूल्य नियंत्रण हटाना ।

कोटा-पद्धति को हटाने का सुझाव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है जबकि मूल्य नियंत्रण हटाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है । जब और जैसे प्रदाय स्थिति में सुधार होगा इन वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण ढीला कर दिया जायेगा । तार के बारे में शीघ्र ही ऐसा करने का विचार है परन्तु चादरों के बारे में ऐसा नहीं किया जायेगा, योंकि चादरों की प्रदाय स्थिति अभी कठिन है । इस समय कीमतों पर से नियंत्रण हटाना उचित नहीं समझा जाता क्योंकि अभी इस्पात की समस्त कमी है ।

(ग) १९६१-६२ में लघु उद्योगों के लिए कोटे के अन्तर्गत कुल मांग और आवंटन इस प्रकार हैं :—

	मीट्रिक टन
मांग	४४०,०३४
आवंटन	१३६,३७०

मांग और आवंटन के आंकड़े निर्बन्धित किस्मों—केवल चादरों और तारों के बारे में हैं । जहां तक अन्य ढील दी गई किस्मों अर्थात् सांरचनिक प्लेटें इत्यादि का सम्बन्ध है, उपभोक्ता या तो बिना किसी प्राधिकार पत्र के नियांत्रित स्टाक होल्डरों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं या अपनी समस्त मांग के लिये लोहा और इस्पात नियंत्रण द्वारा उत्पादकों को व्यादेश भेज सकते हैं ।

(घ) चूंकि इन निर्बन्धित किस्मों की उपलब्धि मांग से कम है, अतः सम्पूर्ण मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकती है । जिस समय नये इस्पात कारखाने अपनी आरम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे तथा अधिक उत्पादन करने लगेंगे उस समय स्थिति अधिक सुधर जायेगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में भविष्य में बढ़ती हुई मांग की तुलना में पर्याप्त क्षमता उत्पन्न करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । उपलब्ध सीमित विदेशी मुद्रा के अन्दर अत्यावश्यक आवश्यकताओं का आयात करने के लिये भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

अनेक करों के स्थान पर उत्पादन-शुल्क

३७८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चारों ओर